साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 22-28 जुलाई 2024 वर्ष-10, अंक-14

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

प्रदेश में अब बैंकों की गाड़ियों में नहीं होंगे पांच करोड़ से ज्यादा कैश

कैबिनेट का अहम फैसलाः क्लाउड पॉलिसी का अनुमोदन

अब स्मार्ट पीडीएस सिस्टम रोकेगा राशन का फर्जीवाड़ा

-मप्र के शासकीय कर्मचारी-पेंशनरों का महंगाई भत्ता चार फीसदी बढ़ाया

-सिरपुर वेटलैंड, रामसर साईट के संरक्षण-प्रबंधन के लिए प्रस्ताव मंजूर

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि वन नेशन, वन राशन कार्ड पीम नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए जरूरी है कि स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाएं। क्योंकि, डुप्लीकेसी भी होती है, एक व्यक्ति के कई स्थान पर कार्ड बन जाते हैं और सही व्यक्ति को उसका हक नहीं मिल पाता, इसलिए, हम स्मार्ट पीडीएस सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी राशि दी है और राज्य सरकार की ओर से मैचिंग ग्रांट दी जाएगी। इस तरह वितरण प्रणाली में किसी भी तरह की गड़बड़ी न हो, इसे रोका जाएगा। इस पर 8.35 करोड़ रुपए 3 वर्ष में खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही कैबिनेट ने एक और अहम फैसला लिया है। इसके तहत बैंकों की गाड़ियों में पांच करोड़ से अधिक की राशि नहीं जा सकेंगे। साथ ही उन गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम होंगी। उसमें बैठने की क्षमता भी तय होगी। साथ ही सुरक्षा में लगी सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए भी मापदंड तय किए गए हैं।

सिक्योरिटी एसेंसी के बने नियम

निजी सुरक्षा एजेंसी के लिए भी राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। इन एजेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों का भी लेखा-जोखा तैयार किया जाएगा। इन एजेंसी को केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा और उसके बाद ही उन्हें अनुमति दी जाएगी। विभिन्न बैंकों की राशि का परिवहन भी इन सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की देखरेख में होता है। राज्य में बैकलॉग के लगभग 17,000 पद खाली थे, जिनमें से 7,000 भरे जा चुके हैं और 10,000 पद अभी खाली हैं। इसके लिए एक वर्ष की अवधि बढ़ाई गई है। 30 जून 2025 तक सभी पदों को भरा जाएगा।

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी

सरकार ने शासकीय सेवकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान में देय मंहगाई भत्ता दर में एक जुलाई 2024 से चार प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। इससे महंगाई भत्ता 46 प्रतिशत हो जाएगा। राज्य शासन के छठवें वेतनमान में कार्यरत शासकीय सेवकों, शासन के उपक्रमों, निगमों, मंडलों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं के राज्य शासन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत चौथे व पांचवें वेतनमान में अनुपातिक आधार पर मंहगाई भत्ते में इजाफा

कर्ज लेने वाले किसानों को छूट

सरकार ने किसानों को सहकारी साख संस्था से मिलने वाले लोन को भरने के समय को एक महीने बढ़ा दिया है। राज्य सहकारी साख संस्थाओं से किसानों को एक साल के लिए जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जाता है। इसके ओवर ड्यू होने पर किसानों के लोन लेने की दक्षता समाप्त हो जाती थी। इसलिए सरकार ने लोन की राशि भरने में एक महीने का इजाफा किया है। इससे सरकार पर 10 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा।

क्लाउड सेवाओं का बेहतर प्रबंधन होगा

सरकार विभागों की विभिन्न योजनाओं के डाटा को सुरक्षित और एक जगह रखने के लिए निजी कंपनियों का सहयोग रहेगा। इसके लिए सरकार क्लाउड बनाने के लिए आईटी कंपनियों से अनुबंध करेगी। इसमें संवेदनशील डाटा सुरक्षित रखा जाएगा। सरकार उच्च स्तर के अधिकारियों की एक टीम बनाएगी। विभागों को क्लाउड की सेवाएं एमपीएसईडीसी के माध्यम से केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। इससे कुल व्यय में बचत होने के साथ ही क्लाउड सेवाओं का बेहतर प्रबंधन भी हो सकेगा।

कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री बनाने से भाजपा के दिग्गजों में असंतोष

उपचुनाव जीतने के बाद अब शाह भी मंत्री पद के दावेदार

भोपाल। जागत गांव हमार

लोकसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत को तो मंत्री पद मिल गया। अब बारी अमरवाड़ा विधानसभा सीट का उपचुनाव जीतने वाले कमलेश शाह की है। कांग्रेस और कमल नाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में भाजपा को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले कमलेश शाह उपचुनाव जीतने के बाद मंत्री पद के दावेदार हो गए हैं। भाजपा आदिवासी वर्ग से आने वाले कमलेश शाह को मंत्री पद का ऑफर देकर ही कांग्रेस से पार्टी में लाई थी। अब तक छिंदवाड़ा जिले की सात विधानसभा सीटों में भाजपा का कोई विधायक न होने से मंत्रिमंडल में भी यहां का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था। अब कमलेश शाह की जीत के बाद माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में एक संक्षिप्त विस्तार और होगा। भाजपा सरकार में कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री बनाए जाने से पार्टी में असंतोष बढ़ रहा है। दरअसल, कांग्रेस से आए नेताओं को मंत्री पद दिए जाने से भाजपा के विधायकों में नाराजगी है।

रावत का पद नहीं हो रहा हजम

लोकसभा चुनाव के दौरान भी लाखों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भाजपा में एंट्री से पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर पड़ा है। कुछ दिन पहले ही मप्र में सीएम डॉ. मोहन यादव ने अपने मंत्रिमंडल का पहला विस्तार किया। इसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे रामनिवास रावत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। ऐसे राजनीतिक निर्णय से भाजपा में कई दिग्गज नाराज हैं।

भार्गव के हाथ खाली

पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव वर्ष 1984 से रहली विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वे भी मंत्री पद के दावेदार हैं। भार्गव इस निर्णय से नाराज बताए गए हैं। कई अन्य नेताओं के विरोध के स्वर भी अब धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं। संजय पाठक भी शिवराज सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ विधायक हैं।

भूपेंद-मलैया भी दौड़ में

मध्य प्रदेश में भूपेंद्र सिंह को शिवराज सिंह चौहान के बाद ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा नेता माना जाता रहा है। भूपेंद्र खुरई विधानसभा सीट से विधायक हैं और सागर सीट से लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। वे भी मंत्री बनने की कतार में हैं। बृजेंद्र प्रताप सिंह हों या जयंत मलैया, पूर्व विस अध्यक्ष डॉ. सीतासरन शर्मा सभी मंत्री बनना चाहते हैं।

जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान 67 औद्योगिक इकाईयों के लोकार्पण-भूमिपूजन के दौरान सीएम बोले

प्रदेश में बनेंगे सेना के टैंक, पन्ना में मिलने वाले हीरे भी यहीं तराशे जाएंगे

भोपाल। । जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश अब औद्योगिक विकास के क्षेत्र में नई छलांग लगाने को तैयार है। जल्द ही मध्य प्रदेश में सेना के लिए टैंक बनने शुरू हो जाएंगे। अशोक लीलैंड और आर्मर्ड व्हीकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा उपकरण बनाने के क्षेत्र में 600 करोड़ का निवेश प्रदेश में होगा। इसके साथ ही पन्ना में बनने वाले हीरों को प्रदेश में ही तराशने की व्यवस्था होगी। यानी गुजरात के सूरत को सीधे-सीधे मध्य प्रदेश चुनौती देने वाला है। जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के दौरान 67 औद्योगिक इकाईयों का लोकार्पण-भूमिपूजन हुआ। इन इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र भी सौंपे गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जबलपुर के सुभाष चंद्र बोस कल्चरल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में उद्योगों से जुड़ी अहम घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि टेक्सटाइल क्षेत्र में अति-आधुनिक स्किल सेंटर की शुरुआत की जाएगी, जिससे विशेष रूप से बहनों को रोजगार प्राप्त होगा। इस वर्ष का दूसरा इंडस्ट्री कॉन्क्लेव जबलपुर में आयोजित हुआ।

रक्षा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की उपस्थिति में 600 करोड़ के निवेश के लिए अशोक लीलैंड और आमज़्डज़ व्हीकल कॉपोरज़ेशन लिमिटेड में करार हुआ। रक्षा क्षेत्र में यह नया कदम है। अब तक मध्य प्रदेश में तोप निमाज़्ण हो रहा था। अब सेना के टैंक भी मध्य प्रदेश में ही बनेंगे।

प्रदेश में तराशेंगे हीरे

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खनिज के क्षेत्र में ओडिशा के बाद मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। खदानों की नीलामी में मध्य प्रदेश की पारदशीज़ प्रक्रिया देश में अग्रणी है। भारत सरकार ने पुरस्कार भी दिया है। प्रदेश के पन्ना जिले में हीरा उत्पादन होता है। अब हीरों को तराशने का कायज़ भी प्रदेश में किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के तमाम दावों की खुली पोलः नई कक्षाओं में प्रवेश के लिए अब तक नामांकन नहीं

प्रदेश में भोपाल नामांकन के मामले में 52वें नंबर पर

देख लो सरकार! स्कूलों को 23 लाख छात्रों का इंतजार

भोपाल। । जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग भले ही लाख दावे करे, लेकिन यह सच है कि प्रदेश मे बच्चों की पढ़ाई से रुचि कम होती जा रही है। यह हम नहीं, बल्कि विभाग के आंकड़े ही बयां कर रहे हैं। नए शिक्षा सत्र को शुरू हुए दो माह हो चुका है, लेकिन अब भी 24 लाख ऐसे छात्र और छात्राएं हैं, जिनके द्वारा नई कक्षा में प्रवेश अब तक नहीं लिया गया है। इनमें सरकारी के अलावा निजी स्कूलों के भी बच्चे शामिल हैं। इनमें सबसे खराब स्थिति सरकारी स्कूलों की है। विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अगर कुल छात्रों की संख्या देखें तो यह 23 लाख 73 हजार है। यह वो विद्यार्थी हैं जिनके द्वारा अब तक नए सत्र में प्रवेश नहीं लिया गया है। इस मामले में भोपाल के स्कूलों की हालत तो और खराब है। यहां पर जिले में बीते साल की तुलना में इस वर्ष 1 लाख 22 हजार विद्यार्थियों का नामांकन कम हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में स्कूलों में प्रवेश को लेकर सरकार के प्रयास कारगर साबित नहीं हो रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के यह हाल तब बने हुए हैं, जबकि विभाग का ही बजट 33 हजार 532 करोड़ बजट है। विभाग की स्थिति नवीन शैक्षणिक सत्र के दो महीने स्कूल लगने के बाद सामने आई है। प्रदेश के सभी जिलों में भोपाल नामांकन में मामले में 52 वें नंबर पर है। यानर सबसे फिसड्डी। अगर बीते साल की बात की जाए तो निजी व सरकारी स्कूलों को मिलाकर कक्षा एक से लेकर 12 तक की कक्षाओं में 13784369 विद्यार्थियों का पंजीयन हुआ था। इसकी तुलना में अब तक प्रदेश में महज 11410911 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ है। यह बीते साल की तुलना में 2373458 कम है।

विद्यार्थियों की होगी मेपिंग

नए शैक्षणिक सत्र 2024-25 की शुरुआत एक अप्रैल से हो चुकी है। एक महीने स्कूल लगने के बाद ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो गए थे। इसके बाद जून के तीसरे सप्ताह से दोबारा स्कूल खुल गए। एक महीने स्कूलों में कक्षाएं लग चुकी हैं। इन आंकड़ों के सामने आने के बाद अब विभाग की नींद खुली तो ऐसे विद्यार्थियों को खोजकर नामांकन करवाने व नामांकित विद्यार्थियों की मेपिंग करवाने के निर्देश दिए हैं।

सभी कक्षाओं में कमी

प्रदेश में गत वर्ष की तुलना में 84.8 फीसदी ही नामांकन हुआ है, यानी 15.65 लाख विद्यार्थियों की कमी है। इसी प्रकार शासकीय शालाओं में नामांकन भी गत वर्ष की तुलना में 87 फीसदी हो पाया है। अर्थात इसमें 8.18 लाख की कमी आई है। इसी प्रकार कक्षा 9 से 12 के नामांकन में भी 8.08 लाख की कमी आई है। कुल मिलाकर कक्षा 1 से 12 के नामांकन में 23.73 लाख की कमी है। प्रदेश की सभी कक्षाओं में कमी आयी है।

सरकारी-निजी स्कूलों के हाल

विशेषकर बीते साल की तुलना में कक्षा 1 में कुल (शासकीय व निजी) 6.63 लाख, शासकीय शालाओं में 6.06 लाख, कक्षा 5 से 6 के बीच कुल (शासकीय व निजी) 1.87 लाख, शासकीय शालाओं में 0.82 लाख, कक्षा 8 से 9 के बीच कुल (शासकीय व निजी) 2.85 लाख, तथा कक्षा 10 से 11 के बीच कुल (शासकीय व निजी) 2.72 लाख की कमी बनी हुई है।

भोपाल की हालत गंभीर

शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार भोपाल की हालत काफी गंभीर है। प्रदेश में पहली से आठवीं तक बीते साल 292377 विद्यार्थियों (शासकीय व निजी) का नामांकन हुआ था, जबकि इस साल अब तक 205950 विद्यार्थियों का ही नामांकन हुआ है। यानी की इसमें बीते साल की तुलना में 70.4 फीसदी यानी 86427 विद्यार्थियों की कमी आयी है। यही वजह है कि इस मामले में भोपाल अन्य जिलों की तुलना में अंतिम पायदान पर पहुंच गया है। भोपाल जिले में पहली से 12वी के नामांकन में बीते साल की तुलना में 122759 विद्यार्थियों की कमी आई है। इतना ही नहीं पहली कक्षा में भी शासकीय स्कूलों में पिछले साल की तुलना में महज 39.17 फीसदी बच्चों नहीं प्रवेश लिया है।

हाईकोर्ट के निर्देश पर भी अमल नहीं

सहकारिता चुनाव पर फिर लगा ब्रेक!

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में 11 साल बाद सहकारिता चुनाव कराने को लेकर बंधी आस एक बार फिर टूटने लगी है। इसकी वजह है इस मामले में शुरू हुई हलचल का शांत हो जाना। विधानसभा सत्र के पहले प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता चुनाव कराने के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया था। इसके बाद से इस क्षेत्र में हलचल तेज हो गई थी, लेकिन अब मामला एक बार फिर से टांय-टांय फिस्स हो गया है। सहकारिता चुनाव के हाल यह तब बने हुए हैं जबकि, हाईकोर्ट सहकारिता के चुनाव कराने के निर्देश दे चुका है। प्रदेश में 4534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, जिन पर सरकार ने प्रशासक बैठा रखे हैं। इनमें से आधी तो डिफाल्टर श्रेणी में आ चुकी हैं। सरकार ने बीते माह प्रदेश में 26 जून से 9 सितंबर के बीच चार चरणों में सहकारिता चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। इससे सरकार की वाहवाही भी खूब हुई थी, लेकिन यह सब अब हवा हवाई ही साबित हुई है। तारीखों की घोषणा करते समय कांग्रेस सरकार पर सहकारिता क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चुनाव न कराने की वजह भी पूर्व सीएम कमलनाथ की सरकार को बताया था। मगर इस बार भी सारी तैयारी कागजी और खानापूर्ति ही साबित हुई है। आज तक न प्राथमिक समितियों के लिए नामांकन शुरू हुआ है और न चुनावों को लेकर गांव और किसानों में कोई हलचल है, बल्कि सब सरकार की मंशा में ही खोट बता रहे हैं। यही नहीं, डिफाल्टर समितियों के चुनाव हो ही नहीं सकते। प्रदेश में आधी समितियां डिफाल्टर हैं। इसके चलते समितियां प्रशासक की देखरेख में ही काम करती रहेंगी और किसानों के लिए दरवाजे अभी बंद ही रहेंगे।

किसान कर्ज माफी ने किया डिफाल्टर

प्रदेश की आधी से अधिक सहकारी समितियां डिफाल्टर हैं। इनमें से अधिकांश समितियां कांग्रेस सरकार की किसान कर्जमाफी योजना के कारण इस हालत में पहुंची हैं। बीते साल विधानसभा होने की वजह से किसानों ने कर्ज माफी की आशा में कर्ज का भुगतान ही नहीं किया,जिसकी वजह से समितियां भी डिफाल्टर की श्रेणी में आ गईं। ग्वालियर, चंबल, विंध्य और बुंदेलखंड अंचल की 90 फीसदी से ज्यादा समितियां डिफाल्टर हैं, तो महाकोशल व नर्मदा पट्टी में 70 प्रतिशत समितिया भी इसी श्रेणी में आ गई हैं।

यह किया था चुनाव कार्यक्रम घोषित

राज्य में सहकारी संस्थाओं के चुनावों के लिए चार चरण में मतदान कराने का कार्यक्रम जारी किया था। इसके अनुसार 26 जून से 9 सितंबर तक इसकी प्रक्रिया चलेगी। सदस्यता सूची जारी करने के बाद 8, 11, 28 अगस्त और 4 सितंबर को मतदान होगा। मतदान के तत्काल बाद मतगणना होगी। सबसे पहले प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों और विभिन्न संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव होंगे। इसके आधार पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक और अपेक्स बैंक के संचालक मंडल का चुनाव होगा।

प्रशासक संभाल रहे समितियां

प्रदेश में 4,534 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं। इनके चुनाव आखिरी बार वर्ष 2013 में हुए थे। इनके संचालक मंडल का कार्यकाल वर्ष 2018 तक था। विधानसभा चुनावों को देखते हुए पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ही इनमें प्रशासक नियुक्त कर दिए थे। फिर कांग्रेस सरकार आई तो तत्कालीन सीएम कमलनाथ ने अपनी किसान कर्ज माफी योजना और लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रशासकों के हाथ में ही कमान रखी। उन्होंने जिला बैंकों में भी प्रशासक बैठा दिए। जैसे-तैसे लोकसभा चुनाव हुए तो सरकार किसान कर्ज माफी योजना में व्यस्त हो गई और चुनाव टाले जाते रहे। कांग्रेस सरकार गिरने के बाद उपचुनाव, कोरोना के कारण चुनाव नहीं हुए। फिर 2023 के चुनाव आ गए प्रशासक ही जिला सहकारी बैंकों को मुखिया बने रहे।

जिम्मेदार अधिकारियों ने राजस्व में भी लगाई सेंध

सरकार के लिए सफेद हाथी बन गए थे सभी चेक पोस्ट

भोपाल। प्रधान संपादक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने परिवहन विभाग के जिन बैरियर (चेक पोस्ट) को बंद करवाया है वे सरकार के लिए सफेद हाथी बनकर रह गए थे। परिवहन विभाग के अधिकारी सरकार की कमाई को सबसे बड़ा साधन बताकर जिन बैरियरों पर वाहनों से अवैध वसूली करवाते वहां से सरकार को कोई विशेष राजस्व नहीं मिल रहा था। गौरतलब है कि परिवहन विभाग सरकार के कमाऊ विभागों में से एक है। इसलिए यह विभाग अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए चारागाह बन गया है। परिवहन के बैरियर पर अवैध कमाई का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस विभाग के एडीजी और स्पेशल डीजी स्तर तक अधिकारी-कर्मचारी परिवहन में नौकरी के लिए लालायित रहते हैं। इस विभाग में आने के लिए मोटी रकम देनी पड़ती है। इसलिए अधिकारियों-कर्मचारियों ने बैरियरों को अपनी अवैध कमाई का जरिया बना लिया था।

इस तरह लगाया चूना- परिवहन विभाग के अवैध वसूली के जिन बैरियर को मुख्यमंत्री ने बंद करा दिया है उन परिवहन बैरियर ने केवल ट्रक चालकों को ही नहीं लूटा, शासन के राजस्व में भी बड़ी सेंधमारी की। 2010-12 में परिवहन विभाग के जिन बैरियर से हर साल शासन को 150 से 180 करोड़ रुपए तक राजस्व मिलता था, अवैध कमाई के फेर में वह घटकर 75 से 90 करोड़ प्रति वर्ष तक ही रह गई।

सहमति से घूसखोरी

पड़ोसी राज्यों से सटी मप्र की सीमाओं पर जिन परिवहन चेकपोस्ट को राजस्व चोरी रोकने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। मोटे अर्थदंड से बचने के लिए ट्रांसपोर्टर और विभागीय अधिकारी की सहमति से यहां घूसखोरी शुरू हो गई। 30 साल पहले अवैध वसूली का जो खेल सौ-दो सौ रुपए से शुरू हुआ था, एक साल पहले तक उसकी कीमत 2000 से 3000 रुपए तक पहुंच गई।

बेहिसाब कमाई

परिवहन विभाग में अवैध वसूली और कमाई का आकलन इसी से किया जा सकता है कि परिवहन विभाग में पदस्थ रहे परिवहन आयुक्त से लेकर आरक्षक तक की चल व अचल संपत्तियां करोड़ों और अरबों में हैं। ये सपत्तियां मप्र के बड़े शहरों भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में भी हैं और मध्यप्रदेश के बाहर भी हैं।

वर्ष 2012 से 2015 तक परिवहन बैरियर से शासन को 150 करोड़ राजस्व मिलता था। 2015-16 के बाद वाहन संख्या बढ़ती गई। 2012 से अब तक यह दो गुना हो गई है। लेकिन राजस्व घट गया। क्योंकि अधिकारी और कर्मचारियों की अवैध वसूली बढ़ गई। सूचना का अधिकार में हमें राजस्व वसूली और बैरियर संचालन पर खर्च की जानकारी नहीं दी जा रही है।

सीएल मुकाती,प्रदेशाध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस

किसानों की समस्या को अपने लिए संजीवनी मान कांग्रेस ने उठाना शुरू किया राजनीतिक लाभ

कहीं सरकार के लिए चिंता का सबब न बन जाएं किसानों की समस्याओं को लेकर हो रहे आंदोलन

किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर हो रहे आंदोलन को कांग्रेस अपने लिए संजीवनी मानकर खुद आंदोलन में कूद पड़ी

श्योपुर । जागत गांव हमार

इन दिनों अचानक से जिले में सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज हो गए हैं। इन आंदोलन में किसानों से जुडी समस्याएं अधिक हैं, वैसे तो इस सीजन में खेती किसानी से जुड़ी समस्या और उनके निराकरण के लिए प्रदर्शन आम बात हैं पर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट के लिए होने वाले उप-चुनाव के चलते इन प्रदर्शनों का विपरीत असर न पड़ जाए इससे भाजपा प्रत्याशी (अभी घोषित नहीं) और प्रदेश नेतृत्व तो चिंतित दिखाई दे रहा है, लेकिन स्थानीय भाजपा नेताओं की चुप्पी आश्चर्य जनक लग रही है। उधर, किसानों से जुडी समस्याओं को लेकर हो रहे आंदोलन को कांग्रेस अपने लिए संजीवनी मानकर खुद आंदोलन में कूद पड़ी है। जबकि अन्य संगठन भी किसानों की समस्याओं के समर्थन में आ गए है।

बिजली, पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव

किसानों से जुड़ी बिजली पानी की समस्या को लेकर युवा कांग्रेस के बैनर तले कांग्रेसियों ने बीते सप्ताह कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर कलेक्टर लोकेश कुमार को सात बिंदुओं वाला ज्ञापन सौंपा, जिसमें रबी सीजन की फसलों के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली आपूर्ति और चंबल नहर से पानी की सप्लाई कराए जाने की मांग प्राथमिकता से अंकित की गई है। कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और किसानों को बिजली पानी मुहैया कराने के बहाने भाजपा सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। ज्ञापन सौंपने के दौरान विधायक बाबू जंडेल, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामभरत मीणा, पूर्व नपा अध्यक्ष दौलत राम गुप्ता, प्रदेश कांग्रेस सचिव राम लखन हिरनी खेड़ा, किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष रितेश सिंह तोमर, राहुल सिंह चौहान, हंसराज रावत, विधायक प्रतिनिधि मांगीलाल फौजी, सिराज दाऊदी, पार्षद सुमेर सिंह बेरवा, इंसाफ खान बड़ौदा आदि मौजूद रहे।

भारतीय किसान यूनियन ने ज्ञापन सौंपकर दी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी

बिजली पानी की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) ने भी प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मूंडला के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चंबल नहर से पानी छोड़े जाने, बिजली के कम वोल्टेज एवं अघोषित बिजली कटौती बंद किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर किसानो के साथ सड़कों पर उतरकर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। इस दौरान नाथू लाल सोई, रामेश्वर आसीदा, हरिमोहन गोहेड़ा, रामराज पच्छीपुरा, बाल मुकंद धनखेड़ा, हनुमान मूंडला , राकेश बगवाड़ा, गौरी शंकर हिरनीखेड़ा, लोकेंद्र, कमलेश, देवकी नंदन, धनराज, महेश, निरंजन आदि किसान मौजूद रहे।

सरपंच एकता महासंघ भी पहुंचा कलेक्ट्रेट, सीएम के नाम दिया ज्ञापन

सरपंच एकता महासंघ ने लामबंद होकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि हाल ही में सरकार ने मनरेगा निर्माण कार्य में पक्के निर्माणों को हटा दिया है। पंचायत अब तक के निर्माण का कोई भुगतान मनरेगा में नहीं होगा जबकि पंचायत में बड़ी संख्या में पक्के निर्माण कार्य चल रहे हैं ऐसी स्थिति में उनका भुगतान अटक जाएगा। ग्राम पंचायत में संचालित पुराने निर्माण कार्य का भुगतान कराया जाए और मनरेगा में बदलाव को स्थगित किया जाए।

बढ़े हुए वेतन को लेकर कोटवार संघ ने दिया ज्ञापन

मध्य प्रदेश कोटवार संघ ने भी वेतन वृद्धि को लेकर बीते सप्ताह कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उल्लेख किया है कि कोटवारों को हर साल वेतन में 500 रुपए की वृद्धि की जाती है। लेकिन इस साल की गई वृद्धि के 500 रुपए वेतन में जोड़कर नहीं दिए जा रहे हैं। नियम अनुसार 500 रुपए वेतन में जोड़कर दिए जाने की मांग करते हुए कोटवारों ने चेतावनी दी है कि वेतन पूरा नहीं देने पर वह हड़ताल कर सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे।

समूह संघ से जुड़ी महिलाएं कर रही आंदोलन

सरकारी स्कूल और आंगनबाड़ियों में पीएम पोषण शक्ति योजना के तहत भोजन नाश्ता पका कर खिलाने वाली वाले महिला स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं द्वारा अपनी मांगों का लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। समूह संघ से जुड़ी महिलाएं प्रदेश व्यापी आंदोलन के चलते प्रदेश के हर जिले में प्रदर्शन कर रही हैं, शीघ्र ही वे भोपाल पहुंचकर जंगी प्रदर्शन करने की बात भी कह रही है।

अतिथि शिक्षक दे रहे भोपाल में धरना

विभिन्न स्कूलों में पढ़ाने का काम कर रहे अतिथि शिक्षक भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय अपनी मांगों को लेकर भोपाल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो घोषणाएं अतिथि शिक्षकों के लिए की थी उन घोषणाओं को सरकार अब पूरा नहीं कर रही है। अतिथि शिक्षकों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच भेद को उजागर करने से भी सरकार की किरकिरी हो रही है।

समस्या निराकरण कराते दिखाई नहीं पड़ रहे भाजपा नेता

इन दिनों किसानों के द्वारा बिजली पानी की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हो गए हैं किसानों की इन मांगों और प्रदर्शनों को कांग्रेस जहां संजीवनी मानकर आंदोलन में खुद को झोंकना शुरू कर दिया है। वहीं भाजपा नेता फिलहाल इन समस्याओं से दूरी बनाए हुए हैं। जबकि इससे पहले भाजपा के नेता खासकर पूर्व विधायक दुर्गा लाल विजय, भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जाट, एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया आदि समस्या ग्रस्त किसानों को लेकर अफसरों के पास बैठे दिखाई पड़ते रहे हैं। ऐसी स्थिति में समस्याओं का निराकरण तो होता ही था। साथ ही पार्टी और सरकार के प्रति किसानों के मन में जो दुराभाव आते थे वह दूर भी होते थे, पर इस बार यह तीनों नेता किसी भी दफ्तर में किसानों के साथ दिखाई नहीं पड़ रहे हैं।

भाजपा-कांग्रेस के जिम्मेदार बोले

सड़क पर उतरेगी कांग्रेस

जब विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं तब तो भाजपा के नेता किसानों के साथ मिलकर अफसरों के बंगलों और दफ्तरों में आते जाते खूब दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आज जब चुनाव को लंबा समय है ऐसी स्थिति में भाजपा नेता किसानों का साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी किसानों का साथ छोड़ा है ना छोड़ेंगी। अगर बिजली पानी की समस्या का जल्द निराकरण नहीं हुआ तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को मजबूर होगी।

रितेश तोमर, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस

भाजपा सरकार को नहीं चिंता

भाजपा की सरकार को किसानों, आमजन और आदिवासियों की बिल्कुल चिंता नहीं है। भाजपा सरकार की सारी योजनाएं दिखावा और उद्योगपतियों को लाभान्वित करने वाली हैं। सरकार की अटल ज्योति योजना को देखना है तो औद्योगिक क्षेत्र में जाकर देखें जहां बिजली की कोई समस्या नहीं है। खेती-किसानी करने वाले ग्रामीणों को बिजली के लो वोल्टेज के चलते परेशान होना पड़ रहा है। धान की फसल रोपाई के समय से ही वोल्टेज के चलते खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। आदिवासियों को तो अंधेरे में सोने को मजबूर होना पड़ रहा है।

छोटे लाल सेमरिया, पूर्व जनपत अध्यक्ष कराहल

सीएम को बताई समस्या

बारिश नहीं होने से बिजली फीडरों पर अधिक लोड बढ़ गया है जिस कारण लो वोल्टेज की समस्या से ग्रसित होना पड़ रहा है। मैं दो दिन पहले ही पांडोला के किसानों के साथ बिजली कंपनी के महाप्रबंधक से मिला था और उनकी समस्याएं बताई थी, किसानों से जुडी समस्या को लेकर भाजपा नेता लगातार अधिकारियों के संपर्क में है आज ही मैंने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और बिजली की समस्या कैसे दूर हो इस बारे में उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई है शीघ्र ही बिजली समस्या का निदान हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मुख्यमंत्री जी ने दिया है।

सुरेन्द्र सिंह जाट, भाजपा जिलाध्यक्ष श्योपुर

जल्द दूर होगी समस्या

यह बात सही है कि क्षेत्र में बिजली की समस्या व्याप्त है, जिससे किसानों को परेशानी होना लाजमी है। हमने सांसदजी के नेतृत्व में श्योपुर क्षेत्र के पूरे भाजपाइयों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें जिले की बिजली समस्या के बारे में अवगत कराया है। भाजपा सरकार ने किसानों की समस्याओं को हमेशा ही प्राथमिकता पर रखकर काम किया है, बिजली पानी की आज प्रदेश में कोई समस्या नहीं है जो समस्या है,वे जल्द ही दूर हो जाएगी।

शशांक भूषण, जिला महामंत्री भाजपा

स्मार्ट हॉर्टिकल्चर या डिजिटल हॉर्टिकल्चर के लाभ

आजकल देश के समृद्ध एवं विकसित प्रदेशों में स्मार्ट हार्टिकल्चर की चर्चा खूब हो रही है। हमारे प्रदेश में स्मार्ट हार्टिकल्चर की जिस पैमाने पर चर्चा होनी चाहिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे प्रदेश के अधिकांश किसान उतने साधन संपन्न नहीं है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि बिहार में स्मार्ट तरीके से बागवानी नहीं हो रही है। हमारे प्रदेश में भी कुछ किसान स्मार्ट तरीके से बागवानी (हार्टिकल्चर) कर रहे हैं। स्मार्ट हार्टिकल्चर या स्मार्ट बागवानी, जिसे स्मार्ट खेती या सटीक कृषि के रूप में भी जाना जाता है, बागवानी में कृषि प्रथाओं को अनुकूलित करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों और डेटा-संचालित दृष्टिकोणों के प्रयोग से संबंधित है।

डॉ एस के सिंह

स्मार्ट बागवानी का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, संसाधन की बर्बादी को कम करना और बागवानी प्रथाओं में समग्र स्थिरता में सुधार करना है। वास्तविक समय डेटा और उन्नत विश्लेषण का लाभ उठाकर, किसान और बागवान सिंचाई, उर्वरक, रोग एवं कीट प्रबंधन और फसल के विकास और स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले अन्य महत्वपूर्ण कारकों के बारे में अधिक

जानकारी पूर्ण निर्णय ले सकते हैं।

स्मार्ट बागवानी के प्रमुख घटक: स्मार्ट बागवानी में पौधों की खेती को अनुकूलित और स्वचालित करने के लिए विभिन्न घटकों और प्रौद्योगिकियों का एकीकरण शामिल है। स्मार्ट बागवानी के कुछ प्रमुख घटक निम्नलिखित है यथा

सेंसर: तापमान, आर्द्रता, प्रकाश की तीव्रता, मिट्टी की नमी और पोषक तत्वों के स्तर जैसी पयाज़्वरणीय स्थितियों के बारे में डेटा एकत्र करने में सेंसर , स्मार्ट बागवानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सेंसर वास्तविक समय डेटा प्रदान करते हैं जो पौधों के विकास की निगरानी और प्रबंधन में मदद करते हैं।

इंटरनेट ऑफथिंग्स: इंटरनेट ऑफथिंग्स तकनीक एक स्मार्ट बागवानी प्रणाली में विभिन्न उपकरणों और घटकों की कनेक्टिविटी को सक्षम बनाती है। यह डेटा विनिमय और उपकरणों के रिमोट कंट्रोल की अनुमति देता है, जिससे बागवानी कार्यों की स्वचालित निगरानी और प्रबंधन की सुविधा मिलती है।

स्वचालित सिंचाई प्रणालियों: स्मार्ट सिंचाई प्रणालियाँ पौधों की इष्टतम पानी की जरूरतों को निर्धारित करने के लिए सेंसर और मौसम डेटा का उपयोग करती हैं। ये प्रणालियाँ पौधों की आवश्यकताओं के आधार पर सिंचाई कार्यक्रम और जल प्रवाह को स्वचालित रूप से समायोजित कर सकती हैं, पानी की बचत कर सकती हैं और कुशल जल प्रबंधन सुनिश्चित कर सकती हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल): आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) पौधों के स्वास्थ्य, विकास पैटनज़ और रोग एवं कीट का पता लगाने के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि और भविष्यवाणियां प्रदान करने के लिए सेंसर से एकत्र किए गए डेटा का विश्लेषण करते हैं। ये प्रौद्योगिकियाँ सक्रिय निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं और बागवानी प्रक्रियाओं को अनुकूलित करती हैं।

वर्टिकल खेती प्रणाली: वर्टिकल खेती में पौधों को खड़ी परतों या संरचनाओं में उगाना शामिल है। इन प्रणालियों में अक्सर एलईडी लाइटिंग, हाइड्रोपोनिक्स और स्वचालित पोषक तत्व वितरण प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों को शामिल किया जाता है, जिससे स्थान का उपयोग और फसल की उपज अधिकतम होती है।

रिमोट मॉनिटरिंग और नियंत्रण: स्मार्ट बागवानी उत्पादकों को मोबाइल एप्लिकेशन या वेब-आधारित प्लेटफार्मों के माध्यम से दूर से अपने संचालन की निगरानी और नियंत्रण करने की अनुमति देता है। वे वास्तविक समय डेटा तक पहुंच सकते हैं, पर्यावरणीय मापदंडों को समायोजित कर सकते हैं और गंभीर स्थितियों या सिस्टम विफलताओं के बारे में अलर्ट या सूचनाएं प्राप्त करते हैं।

डेटा एनालिटिक्स: स्मार्ट बागवानी प्रणालियों में डेटा का संग्रह विस्तृत विश्लेषण और व्याख्या को सक्षम बनाता है। डेटा

एनालिटिक्स तकनीक निर्णय लेने, संसाधन आवंटन को अनुकूलित करने और समग्र उत्पादकता में सुधार करने के लिए पैटर्न, रुझान और सहसंबंधों की पहचान करने में मदद करती हैं।

रोबोटिक सिस्टम: रोपण, कटाई, छंटाई और फसल के रखरखाव जैसे कार्यों के लिए स्मार्ट बागवानी में रोबोट और स्वचालित मशीनरी का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। ये प्रणालियाँ श्रम आवश्यकताओं को कम करती हैं, दक्षता बढ़ाती हैं और सटीक कृषि तकनीकों को सक्षम बनाती हैं।

ऊर्जा प्रबंधन: स्मार्ट बागवानी ऊर्जा खपत को अनुकूलित करने, लागत कम करने और टिकाऊ प्रथाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा प्रबंधन प्रणालियों को एकीकृत करती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, ऊर्जा-कुशल प्रकाश व्यवस्था और स्मार्ट पावर प्रबंधन तकनीकों का उपयोग शामिल होता है।

मोबाइल एप्लिकेशन: मोबाइल एप्लिकेशन उत्पादकों को उनकी बागवानी प्रणालियों की निगरानी और नियंत्रण के लिए उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करते हैं। इन ऐप्स में अक्सर वास्तविक समय डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, अलर्ट, फसल प्रबंधन उपकरण और सिस्टम नियंत्रण तक रिमोट एक्सेस जैसी सुविधाएं शामिल होती हैं। ये सभी घटक एक स्मार्ट बागवानी पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए मिलकर काम करते हैं जो पौधों की खेती में उत्पादकता, संसाधन दक्षता और स्थिरता को बढ़ाता है।

स्मार्ट बागवानी के लाभ: स्मार्ट बागवानी, जिसे सटीक या डिजिटल कृषि के रूप में भी जाना जाता है, फसलों की खेती और प्रबंधन को अनुकूलित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों और डेटा विश्लेषण के उपयोग के बारे में बताता है। स्मार्ट बागवानी के कई फायदे हैं जैसे

उत्पादकता में वृद्धि एवं उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त होते हैं: स्मार्ट बागवानी किसानों को तापमान, आर्द्रता और प्रकाश की स्थिति जैसे विभिन्न पर्यावरणीय कारकों की निगरानी और नियंत्रण करने में सक्षम बनाती है। इन मापदंडों को अनुकूलित करके, किसान अपनी फसलों के लिए आदर्श बढ़ती परिस्थितियाँ बना सकते हैं, जिससे उत्पादकता में वृद्धि और अधिक पैदावार होती है साथ ही साथ उत्पाद उच्च गुणवत्ता युक्त होते है।

संसाधन दक्षता: स्मार्ट बागवानी पौधों तक पानी, उवज़्रक और पेस्टिसाइड को सटीक रूप से पहुंचाने के लिए सेंसर और स्वचालन प्रणाली का उपयोग करती है। यह लक्षित दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि संसाधनों का कुशलतापूवज़्क उपयोग किया जाए, अपशिष्ट को कम किया जाए और कृषि के पयाज़्वरणीय प्रभाव को कम किया जाए। यह किसानों को पानी, ऊजाज़ और इनपुट से जुड़ी लागत बचाने में भी मदद करता है।

फसल निगरानी और प्रबंधन: ड्रोन या उपग्रह जैसी रिमोट सेंसिंग प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से, किसान अपनी फसलों के स्वास्थ्य, वृद्धि और विकास के बारे में वास्तविक समय की जानकारी एकत्र कर सकते हैं। यह डेटा बीमारियों, पोषक तत्वों की कमी या रोग कीट संक्रमण का शीघ्र पता लगाने में सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर फसल प्रबंधन की अनुमति मिलती है।

वास्तविक समय में निर्णय लेना: स्मार्ट बागवानी किसानों को उनकी फसलों और संचालन के बारे में वास्तविक समय डेटा और अंतदृष्टि प्रदान करती है। यह उन्हें समय पर निर्णय लेने और बदलती परिस्थितियों या चुनौतियों का तुरंत जवाब देने में सक्षम बनाता है। सटीक और अद्यतन जानकारी तक पहुंच प्राप्त करके, किसान अपनी उत्पादन रणनीतियों को अनुकूलित कर सकते हैं और जोखिमों को कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर, स्मार्ट बागवानी कई लाभ प्रदान करती है जो कृषि में उत्पादकता, संसाधन दक्षता, स्थिरता और निणज़्य लेने की क्षमता को बढ़ाती है। प्रौद्योगिकी और डेटा-संचालित दृष्टिकोणों के संयोजन से, इसमें कृषि पद्धतियों में क्रांति लाने और अधिक कुशल और टिकाऊ खाद्य उत्पादन प्रणाली में योगदान करने की क्षमता है

कृषि के क्षेत्र में भी बना सकते है बेहतरीन करियर

कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए, आपको सही शिक्षा और प्रशिक्षण लेना ज़रूरी है। इसके लिए, आप देश के कई कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर, और डॉक्टरेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। 12वीं के बाद कृषि में ग्रेजुएट करने के लिए, चार साल का बीएससी-एग्रीकल्चर/बीएससी-एग्रीकल्चर कोर्स करना होता है। यदि आप कृषि क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिक फसलों, पौधों और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान करते हैं। कृषि इंजीनियर कृषि मशीनरी, सिंचाई प्रणाली और भंडारण सुविधाओं के डिजाइन और विकास में काम करते हैं।

कृषि के क्षेत्र में आज के समय में कई विकल्प मौजूद हैं। छात्र-छात्राएं इस फील्ड में कृषि वैज्ञानक से लेकर कृषि विपणन विशेषज्ञ के रूप में करियर बना सकते हैं।

आज के टाइम पर कृषि का काफी महत्व बढ़ गया है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और यहां कृषि क्षेत्र में अनेक अवसर उपलब्ध हैं। अगर आप भी इस फील्ड में रुचि रखते हैं और इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके पास कई ऑप्शन मौजूद हैं।

कृषि क्षेत्र में सफल करियर के लिए सही शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना बेहद जरूरी है। आप देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में सफल करियर के लिए सही शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करना बेहद जरूरी है। आप देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं के बाद कृषि में ग्रेजुएट करने के लिए 4 साल का कोर्स करना होता है, जिसे बीएससी-एग्रीकल्चर/बीएससी-एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये कोसज़ कृषि क्षेत्र का एक प्रोफेशनल कोर्स है, जिसके लिए 12वीं एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से पास होना जरूरी है।

12वीं के बाद कृषि में ग्रेजुएट करने के लिए 4 साल का कोर्स करना होता है, जिसे बीएससी-एग्रीकल्चर/बीएससी-एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ये कोसज़ कृषि क्षेत्र का एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए 12वीं एग्रीकल्चर या बायोलॉजी से पास होना जरूरी है।

कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएट करने के बाद आपको सरकारी और निजी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। यदि आप कृषि क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कर सकते हैं।

कृषि क्षेत्र में ग्रेजुएट करने के बाद आपको सरकारी और निजी क्षेत्रों में बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे। यदि आप कृषि क्षेत्र में कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा के लिए पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कर सकते हैं।

कृषि वैज्ञानिक फसलों, पौधों और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान करते हैं। कृषि इंजीनियर कृषि मशीनरी, सिंचाई प्रणाली और भंडारण सुविधाओं के डिजाइन और विकास में काम करते हैं। पशुपालन विशेषज्ञ पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन का प्रबंधन करते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और प्रथाओं के बारे में शिक्षित करते हैं।

कृषि वैज्ञानिक फसलों, पौधों और मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए अनुसंधान करते हैं। कृषि इंजीनियर कृषि मशीनरी, सिंचाई प्रणाली और भंडारण सुविधाओं के डिजाइन और विकास में काम करते हैं। पशुपालन विशेषज्ञ पशुओं के स्वास्थ्य, पोषण और प्रजनन का प्रबंधन करते हैं। कृषि विस्तार अधिकारी किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों और प्रथाओं के बारे में शिक्षित करते हैं।

खाद्य वैज्ञानिक खाद्य प्रसंस्करण, संरक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में काम करते हैं। कृषि अर्थशास्त्री कृषि उत्पादन, विपणन और नीति का विश्लेषण करते हैं। कृषि विपणन विशेषज्ञ किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। ग्रामीण विकास विशेषज्ञ ग्रामीण समुदायों के विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। खाद्य वैज्ञानिक खाद्य प्रसंस्करण, संरक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण में काम करते हैं। कृषि अथज़्शास्त्री कृषि उत्पादन, विपणन और नीति का विश्लेषण करते हैं। कृषि विपणन विशेषज्ञ किसानों को अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं। ग्रामीण विकास विशेषज्ञ ग्रामीण समुदायों के विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं।

बिना आधार के नहीं मिलेगा खराब फसल का मुआवजा

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के किसानों को काफी राहत मिलती है। इस योजना के जरिए किसानों को उनके फसलों के हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे किसान नुकसान से बच जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बीमा क्लेम करने के लिए आधार नंबर होना बहुत जरूरी है।

किसानों की सहायता के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से तमाम अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं से किसानों को कई प्रकार से लाभ मिलता है। इन्हीं में से एक स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना, जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से राहत दिलाने के लिए चलाया जाता है। इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से फसल का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आधार के बिना किसानों को खराब फसल का मुआवजा नहीं मिलेगा। आपको ये भी जानना चाहिए कि प्रीमियम भुगतान का नियम क्या है। आइए जानते हैं।

इन फसलों में पर मिलेगा बीमा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में बोई जाने वाली कई फसलों पर बीमा का कवरेज दिया जाता है. इसमें सिंचित धान, असिंचित धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, मूंग, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, कपास, अरहर और कोदो-कुटकी शामिल हैं. इसके साथ ही फसल की बुवाई के बाद अगर किसान को नुकसान होता है तो बीमा कवरेज किसान को मिलता है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल कटाई के बाद भी नुकसान का कवर मिलता है।

बीमा के लिए आधार है जरूरी

1. सभी किसानों का बीमा कवरेज भारत सरकार के पोर्टल pmfby.gov.in पर होता है.
2. प्रीमियम राशि केवल NCIP-Portal के भुगतान गेटवे Pay-Gov द्वारा ही भेजी जाएगा।
3. खराब फसल का मुआवजा लेने के लिए सभी किसानों का आधार नंबर होना अनिवार्य है।

31 जुलाई तक है लास्ट डेट: मध्य प्रदेश के किसान अपनी खरीफ फसलों के लिए 31 जुलाई तक बीमा करवा सकते हैं। किसान अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए फसल बीमा पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं, समय पर फसल नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने के कारण किसानों को परेशानी होती है। ऐसे में किसान इस पोर्टल पर अपनी खरीफ फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

कई राज्य के किसान धान की खेती में अधिक पानी खर्च होने के कारण इससे दूरी बनाने लगे हैं, खाद का कमाल...

अब एक सिंचाई में तैयार होगी धान की फसल

भोपाल। जागत गांव हमार

धान खरीफ की प्रमुख फसल है। देश के कई राज्यों में इसकी खेती की जाती है। लेकिन कई राज्य के किसान धान की खेती में अधिक पानी खर्च होने के कारण इससे दूरी बनाने लगे हैं। लगातार गिरते भू-जल स्तर के कारण सरकार भी किसानों को धान की जगह अन्य फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है जिसमें पानी कम खर्च होता हो। हरियाणा सरकार की ओर से धान की खेती छोड़कर दूसरी फसल की खेती करने वाले किसानों को सब्सिडी भी दी जा रही है। ऐसे में धान की खेती में कम पानी खर्च हो इसके लिए धान की नई-नई किस्में भी खोजी जा रही हैं। इसके अलावा नई तकनीक से खेती करने की सलाह दी जा रही है। इसी कड़ी में एक ऐसी तकनीक खोजी गई है जिसमें विशेष खाद का इस्तेमाल करके किसान एक सिंचाई में धान की खेती कर सकते हैं।

धान की खेती में कितना लगता है पानी- धान की खेती में चार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है जिसमें बहुत सा पानी खर्च हो जाता है जिससे धान की लागत बढ़ जाती है। एक अनुमान के मुताबिक एक किलो धान पैदा करने के लिए करीब 3,000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो धान की खेती में अन्य फसलों की अपेक्षा सबसे अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है।

किस खाद के इस्तेमाल से धान में कम लगेगा पानी

यह एक ऐसी खाद है जो नारियल से बनाई जाती है। इस खाद में नारियल के छिलकों और डाभ का इस्तेमाल किया जाता है। इस खाद को घर पर आसानी से बनाया जा सकता है। नारियल और डाभ के प्रयोग से आप कम पानी के खर्च में धान की खेती कर सकते हैं। इससे आपके धान की लागत तो कम होगी ही, साथ ही पानी की बचत भी होगी जिससे आप अन्य फसल उगाने में इस्तेमाल कर पाएंगे।

कैसे तैयार की जाती है नारियल व डाभ से खाद- नारियल और डाभ को पहले एक साथ मिलाया जाता है और इसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब यह अच्छे से सड़ जाती है तो यह खाद का काम करेगी। अब आपको इस सड़ी हुई खाद को अपने खेत में छिड़कना होगा। इस तरह आप कम खचज में धान की खेती के लिए घर पर सस्ती खाद तैयार कर सकते हैं।

नारियल खाद से कैसे होगी धान की खेती में पानी की बचत

नारियल के छिलकों और डाभ से बनी यह प्राकृतिक खाद धान के खेत में सिंचाई के पानी को सोख लेती है जिससे खेत में लंबे समय तक नमी बनी रहती है। ऐसे में किसान को धान की फसल में चार सिंचाई की जगह एक ही सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। शेष तीन सिंचाई का काम यह खाद कर देती है। इस खाद के प्रयोग से पानी व पैसों की बचत होती है और धान की पैदावार भी अच्छी होती है।

कितनी मात्रा में करें नारियल खाद का इस्तेमाल

यदि आप अपने धान के खेत में नारियल खाद की एक किलोग्राम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं तो यह एक किलोग्राम खाद करीब 10 लीटर पानी सोख लेती है। ऐसे में किसान अपने खेतों के आकार के हिसाब से इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह खाद प्राकृतिक रूप से तैयार होने के कारण इसका कोई विपरीत असर फसलों की पैदावार पर नहीं पड़ता है। इस तरह आप नारियल खाद का इस्तेमाल धान की खेती में करके पानी व पैसा दोनों की बचत कर सकते हैं।

धान की खेती में कितना लगता है रासायनिक उर्वरक

धान की खेती में किस्मों के हिसाब से खाद व उर्वरक की मात्रा देनी होती है। इसमें धान की कम अवधि वाली किस्मों के लिए प्रति हैक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश की मात्रा दी जाती है। वहीं धान की मध्यम अवधि वाली किस्मों में प्रति हैक्टेयर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा दी जाती है। इसके अलावा धान की लंबी अवधि की किस्मों के लिए 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस तथा 80 किलोग्राम पोटाश की मात्रा डालना पर्याप्त रहता है।

सोयाबीन फसल में खरपतवार प्रबंधन हेतु किसानों को जरूरी सलाह

कृषि वैज्ञानिक ने बताया कैसे करें फसल की देखभाल, जिससे मिल सके अच्छा उत्पादन

भोपाल। जागत गांव हमार

सोयाबीन की फसल में कीट रोग एवं खरपतवार का नियंत्रण समय पर नहीं करने से फसल उत्पादन प्रभावित होता हैं। सोयाबीन की फसल में प्रमुख रूप से संकड़ी पत्ती या एक दलपत्रीय एवं चौड़ी पत्ती या दो दलपत्रीय खरपतवार पाए जाते हैं। जैसे संवा घास, दूब घास, बोकना, बोकनी, मोथा, दिवालिया, छोटी बड़ी दुद्धी, हजार दाना और सफेद मुर्ग आदि।

कृषि विज्ञान केन्द्र आगर-मालवा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ आर पी एस शक्तावत ने बताया कि फसल की प्रारंभिक अवस्था में 45 से 60 दिन तक फसल खरपतवार मुक्त रहनी चाहिए। इसके लिए 15 से 20 दिन की स्थिति में बेल चलित डोरा या कल्पा चलाना चाहिए या निदाई गुड़ाई करनी चाहिए। लगातार बारिश की स्थिति में खरपतवार प्रबंधन रसायन के छिड़काव द्वारा किया जा सकता है।

सफल खरपतवार नियंत्रण के लिए आवश्यक सावधानियां- किसान केवल अनुशंसित खरपतवारनाशी का ही उपयोग करें। खरपतवारनाशकों के छिड़काव हेतु 500 लीटर पानी प्रति हैक्टेयर का उपयोग करें। खरपतवारनाशकों के छिड़काव हेतु फ्लैट फेन या फ्लड जेट नोजल का ही उपयोग करें। खरपतवारनाशकों के छिड़काव नम या भुरभुरी मिट्टी में ही करें। सुखी मिट्टी पर छिड़काव नहीं करें। एक ही खरपतवारनाशी का उपयोग बार-बार नहीं करें। रसायन चक्र को अपनाएं। एक से अधिक खरपतवारनाशक या उनका अन्य किसी खरपतवारनाशकों या कीटनाशक के साथ मिश्रित उपयोग कदापि नहीं करें, जो अनुशंसित नहीं हो। इससे सोयाबीन के पूर्णत: खराब होने की संभावना रहती है। बोवनी के पूर्व या बोवनी के तुरंत पश्चात् खरपतवारनाशियों के उपयोग किए जाने की स्थिति में 20 से 25 दिन की स्थिति में बेल चलित डोरा या कल्पा चलाना चाहिए। सोयाबीन की खड़ी फसल में उपयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशियों की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से कुछ इस प्रकार से करें।

बोवनी के 10 से 12 दिन बाद

- क्लोरम्यूरोंन इथाइल 25 डब्लू पी+ सर्फेक्टेंट 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर,
- बेंटाझोन 48 एस एल 2 लीटर प्रति हेक्टेयर
- बोवनी के 15 से 20 दिन बाद
- इमेजाथापेयर 10 एस एल + सर्फेक्टेंट 1 लीटर प्रति हेक्टेयर
- इमेजाथापेयर 70 डब्लू जी + सर्फेक्टेंट 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर
- क्विजलोफ़ॉप इथाइल 5 ई सी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर
- क्विजलोफ़ॉप पी इथाइल 10 ई सी 450 मीलीलीटर प्रति हेक्टेयर
- फिनाक्सीफ़ॉप पी इथाइल 9 ई सी 11 लीटर प्रति हेक्टेयर, क्विजलोफ़ॉप पी टेफ्यूरिल 41 ई सी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर
- फ्ल्यूआजीफ़ॉप पी ब्यूटाइल 4 ई सी 1।5 लीटर प्रति हेक्टेयर
- हेलॉक्सीफ़ॉप आर मिथाइल 5 ई सी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर
- प्रोपाक्विजाफ़ॉप 10 ई सी 750 मीलीलीटर प्रति हेक्टेयर
- क्लेथोडीयम 25 ई सी 750 मीलीलीटर प्रति हेक्टेयर, फ्लूथियासेट मिथाइल 3 ई सी 125 मीलीलीटर प्रति हेक्टेयर

पूवज़ मिश्रित खरपतवारनाशी

फ्ल्यूआजीफ़ॉप पी ब्यूटाइल + फोमेंसाफेन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर
- इमेजाथापेयर + इमेजामॉक्स 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर, प्रोपाक्विजाफ़ॉप + इमेजाथापेयर 2 लीटर प्रति हेक्टेयर
- सोडियम एसीफ्लोरफेन + क्लोडिनाफ़ॉप प्रोपारजिल 1लीटर प्रति हेक्टेयर
- फोमेंसाफेन + क्विजलोफ़ॉप इथाइल5 लीटर प्रति हेक्टेयर
- क्विजलोफ़ॉप इथाइल + क्लोरम्यूरोंन इथाइल + सफेज़क्टेन्ट 375 मिली + 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर

अब रेशम के धागे से बनेंगी दवाइयां, क्रीम और ड्रेसिंग बैंडेज: किसानों को मिलेगा फायदा

भोपाल। देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित उद्योग खोलने के साथ ही किसानों के द्वारा उपजाए जाने वाले कच्चे माल का उद्योगों में इस्तेमाल करना है। इस कड़ी में रेशम उत्पादक किसानों को लाभ मिल सके इसके लिए सरकार ने रेशम से दवाइयाँ, क्रीम और ड्रेसिंग बैंडेज बनाने का निणज्य लिया है।

मध्यप्रदेश के कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री दिलीप जायसवाल ने नर्मदापुरम संभाग में जारी रेशम विकास गतिविधियों के अवलोकन के दौरान निर्देश दिये थे कि रेशम उत्पादों का प्रयोग कर रेशम धागे से दवाईयों के उत्पादन में भी किया जाये। जैसा कि फिलहाल रेशम के वस्त्रों का उपयोग सदियों से किया जा रहा है।

रेशम के धागों का इस्तेमाल होगा दवाइयाँ बनाने में

अब रेशम के धागों का उपयोग दवाईयां एवं सर्जिकल ड्रैसिंग बनाने के लिये किया जायेगा। इसके लिये किसानों का सारा का सारा ककून य कर लिया जाएगा। इससे रेशम से समृद्धि योजना के तहत रेशम उत्पादों, के नियाज़्त को बढ़ावा मिलेगा। अब रेशम धागे से ीम, बैंडेज, पावडर, प्रोटीन, सौंदर्य उत्पाद भी बनाए जाएंगे। सिल्क बैंडेज होने से ऑप्टिमाइज हीलिंग होगी और इससे 30 प्रतिशत व्यय भार भी कम आयेगा और रिकवरी भी जल्द होगी। उल्लेखनीय है कि ड्रग्स कंट्रोलर, भारत सरकार द्वारा गत 16 नवंबर 2020 को आईंटमेन्ट्स, जैल, एजीफोम, फाइब्रोहिल उत्पादों को मान्यता दे दी गयी है। मान्यता मिलने से एम्स एवं गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा इसका अधिकाधिक उपयोग किया जा रहा है।

कंपनियों को भेजा जाएगा कच्चा माल

कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री जायसवाल के निदेज़्श पर नर्मदापुरम संभाग से रेशम से दवाईयां एवं सर्जिकल ड्रेसिंग बनाने के लिये अधिकाधिक कच्चा माल कम्पनियों को भेजा जायेगा। इससे रेशम उत्पादक किसानों को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। भोपाल के प्रख्यात सजज़्न डॉ. अभिजीत देखमुख द्वारा इस संबंध में मेंटर के रूप में कार्य किया जा रहा है। इस तरह के उत्पाद आने से अब रेशम उत्पादक किसानों और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग दोनों को लाभ मिलेगा।

जैव विविधता शो में देश के जीआई टैग प्राप्त ऑम की किस्मों का प्रदर्शन

सुन्दरजा आम को मिली राष्ट्रीय स्तर पर पहचान

रीवा। जागत गांव हमार

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि महाविद्यालय रीवा (म.प्र.) अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना, फल अनुसंधान केन्द्र कुठुलिया द्वारा 96 वां भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस 15 और 16 जुलाई 2024 को एन.ए.एस.सी. काम्पलेक्स पूसा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । इस अवसर पर आम की जैव विविधता शो में देश के लगभग 400 प्रजाति एवं देश की भौतिक संकेतक जी.आई. टैग प्राप्त ऑम केशर (गुजरात) चौसा (हरदोई उ.प्र.) अल्फान्सो (महाराष्ट्र) दशहरी (मलीहाबाद) लंगड़ा (बनारस) एवं सुदरजा (म.प्र.) लगाई गई थी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केन्द्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। फ्ल अनुसंधान केन्द्र के प्रभारी डॉ. टी. के. सिंह द्वारा रीवा सुन्दरजा मैंगो का प्रदर्शन मुख्य अतिथि के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उन्होंने सुन्दरजा आम की प्रशंशा करते हुए उसके क्षेत्र को बढाने एवं निर्यात के लिए कहा । निदेशक डॉ. टी. दामोदरन केन्द्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ द्वारा सुन्दरजा आम को अन्य आमों के साथ निर्यात करने के लिए कहा। अखिल भारतीय फल अनुसंधान परियोजना, परियोजना समन्वयक डॉ. प्रकाश पाटिल सुन्दरजा आम को निर्यात करने सी.आई.एस.एच. के साथ किया जाय। इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. हिमांशू पाठक उप महानिदेषक उद्यान डॉ. संजय सिंह ए.डी.जी. डॉ. वी.बी. पटेल आदि उपस्थित रहे ।

इस उपलब्धि पर कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता प्रोफेसर डॉ. एस. के त्रिपाठी, डॉ. बी. एम. मौर्या, डॉ. रघुराज किशोर तिवारी, डॉ. आर. पी. जोशी, डॉ. एस. एम. कुर्मवंशी, डॉ. अखिलेश कुमार विभागाध्यक्ष (कीट विज्ञान) , डॉ. वी के. सिंह विभागाध्यक्ष (उद्यान) , डॉ. अभिषेक सोनी, गौरव नामदेव एवं कृषि विज्ञान केन्द्र के सभी वैज्ञानिकों ने शुभकामनाएं एवं बधाइयां दी।

खरीफ फसल बुवाई में भारी वृद्धि, 704 लाख हेक्टेयर के पार

अच्छे उत्पादन की उम्मीद, उपभोक्ताओं को मिल सकती है महंगाई से राहत

भोपाल। जागत गांव हमार

मानसून सीजन में हुई अच्छी बारिश से खरीफसीजन की फसलों के बुआई रकबे में भारी वृद्धि हुई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी किए गए आँकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक चावल, दाल, तिलहन सहित कपास और गन्ने के बुआई रकबे में बढ़ोतरी हुई है। हालाँकि अभी श्री अन्न यानि के मोटे अनाज का बुआई रकबा पिछड़ा हुआ है। बुआई रकबे में हुई वृद्धि को देखते हुए इस साल देश में अच्छे उत्पादन की उम्मीद है, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिल सकती है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक़ इस साल धान यानि की चावल के बुआई रकबे में भी काफी वृद्धि हुई है। पिछले साल 15 जुलाई तक चावल का बुआई रकबा जहां 95.78 लाख हेक्टेयर था जो इस साल बढ़कर 115.64 प्रतिशत हो गया है।

दलहन फसलों के बुआई रकबे में हुई वृद्धि

इस साल दलहन के बुआई रकबे में काफी वृद्धि दजज़ की गई है। इस साल दलहन फसलों का बुआई रकबा 49.50 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 62.32 लाख हेक्टेयर हो गया है। दलहन फसलों में अरहर के बुआई रकबे में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। इस साल अरहर फसल का बुआई रकबा 9.66 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 28.14 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं मूंग एवं अन्य दालों के बुआई रकबे में कमी आई है। मूंग दाल का बुआई रकबा इस बार 19.75 लाख हेक्टेयर से घटकर 15.79 लाख हेक्टेयर रह गया है।

मोटे अनाज के बुआई रकबे में आई कमी

इस साल 15 जुलाई तक मोटे अनाजों के बुआई रकबे में कमी आई है। इस साल मोटे अनाज का बुआई रकबा 104.99 लाख हेक्टेयर से घटकर 97.64 लाख हेक्टेयर हो गया है। मोटे अनाज में सबसे अधिक कमी बाजरा में आई है वहीं मक्का के बुआई रकबे में वृद्धि दजज़ की गई है। इस साल बाजरे का बुआई रक़बा 50.9 लाख हेक्टेयर से घटकर 28.32 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं मक्का का बुआई रकबा 43.84 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 58.86 लाख हेक्टेयर हो गया है।

तिलहन के बुआई रकबे में हुई वृद्धि

वहीं इस साल तिलहन फसलों के बुआई रकबे में भी वृद्धि हुई है। इस साल तिलहन फसलों का बुआई रकबा 115.08 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 140.43 लाख हेक्टेयर हो गया है। तिलहन फसलों में सबसे अधिक वृद्धि इस बार सोयाबीन में हुई है। सोयाबीन का बुआई रकबा 82.44 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 108.10 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। वहीं मूंगफली के बुआई रकबे में मामूली वृद्धि हुई है। इसके अलावा नकदी फसलों में सबसे अधिक वृद्धि कपास की फसल में हुई है। कपास का बुआई रक़बा 93.02 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 95.79 लाख हेक्टेयर हो गया है। वहीं गन्ना फसल के बुआई रकबे में भी मामूली वृद्धि हुई है। गन्ना का बुआई रक़बा इस साल 56.86 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 57.68 लाख हेक्टेयर हो गया है।

इंदौर ने बनाया विश्व रिकार्ड

इंदौर सांसद लालवानी ने ड्रोन से लगाये बीज

भोपाल। जागत गांव हमार

खेती में ड्रोन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। किसान ड्रोन की मदद से ना केवल नैनो उर्वरकों एवं दवाओं का छिड़काव फसलों पर कर सकते हैं बल्कि बीज लगाने में भी ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। इस कड़ी में इंदौर के सांसद शंकर लालवानी इंदौर को हरित बनाने के लिए अब ड्रोन की मदद ले रहे हैं। सांसद लालवानी ने विभिन्न क्षेत्रों में पीपल के बीजों का रोपण किया है। इंदौर के ड्रोन बनाने वाले स्टार्टअप पाइज़र्व टेक्नोलॉजी द्वारा अनोखा ड्रोन तैयार किया है।

सांसद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इंदौर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही कई इलाके ऐसे होते हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप से पेड़ लगाना संभव नहीं होता इसलिए इंदौर के स्टार्टअप के बारे में जब मुझे जानकारी मिली तो हमने पीपल के बीजों का रोपण ऐसी जगह पर किया जहां पेड़ लगाना मुश्किल काम है।

सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ है पीपल

इंदौर के सांसद लालवानी ने कहा कि बारिश का मौसम बीजारोपण के लिए सबसे अनुकूल होता है। पीपल सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला वृक्ष माना गया है इसलिए पीपल लगाने की कोशिश की गई है। सांसद लालवानी ने बताया कि ड्रोन से बीज लगाने की तकनीक के माध्यम से इंदौर के आसपास कई क्षेत्रों को हरा-भरा किया जा सकता है और कृषि के क्षेत्र में भी इसकी अथाह संभावनाएँ है। पाइज़र्व टेक्नोलॉजी के सीटीओ अभिषेक मिश्रा ने बताया की ड्रोन से सीधे बीजरोपण करने का प्रयोग भारत में पहली बार हुआ है। इससे पहले सीड बॉल गिराने के प्रयोग हुए हैं। साथ ही ये पूरी तरह से मेड इन इंडिया ड्रोन है और हमने उसे बीजारोपण के लिए अपग्रेड किया है।

नौकरी छूटी, तो आधा बीघा से शुरू की नर्सरी-

आज 6 बीघा में बागवानी, आम की 9 किस्में और अमरूद की 8 किस्में

गुना। जागत गांव हमार

गुना में एक युवक ने नौकरी छूट जाने के बाद 1998 में कुछ डिसमिल जमीन पर नर्सरी शुरू की। आज 6 बीघा में वे नर्सरी संचालित कर रहे हैं। इसमें आम की 9 किस्में, अमरूद की 8 किस्में, नींबू, सीडलैस नींबू, जामुन, आंवला, गुलाब की विभिन्न किस्में सहित कई पौधे उगा रहे हैं। इसमें उन्हें सालाना करीब 5 लाख रुपए की इनकम हो रही है। वे न

केवल जिले में बागवानी को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि लोगों को रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर अशोकनगर रोड पर मावन गांव में वाटिका नर्सरी है। बारिश का मौसम होने से लोग यहां पौधे लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही, सरकार का एक पेड़ मां के नाम अभियान भी चल रहा है, इसलिए सरकारी कर्मचारी भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं।

लखनऊ-नासिक से मंगवाता हूं ऑथेंटिक वैरायटी

नर्सरी में आम की 9 किस्में, अमरूद की 8 किस्में, नींबू, सीडलैस नींबू, जामुन, आंवला और गुलाब की विभिन्न किस्मों सहित कई पौधे मिलते हैं। मैं अमरूद के कुछ पौधे लखनऊ से मंगवाता हूं। नींबू के कुछ पौधे नासिक से मंगवाता हूं। जहां भी प्रोडक्शन होता है, वहां से ऑथेंटिक वैरायटी मंगवाता हूं। हमारे पास दूर - दूर से किसान आते हैं। उनका भरोसा ही हमारी पूंजी है।

जिले की एकमात्र ISO अप्रूव्ड नर्सरी

मेरे यहां अमरूद, देसी आम, कुछ नींबू के अलावा डेकोरेशन के पौधे तैयार किए जाते हैं। इसमें ये निश्चित नहीं रहता है कि एक साल में कितनी आय हो जाएगी। जो इनकम है, वो जमीन पर दिखती है। स्टॉक के रूप में दिखती है। इसमें पूंजी स्टॉक के रूप में रहती है। इसमें मटेरियल, लेबर सहित करीब 7 - 8 लाख रुपए सालाना खर्च हो जाते हैं। सालभर में करीब 5 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। यह गुना की एकमात्र नर्सरी है, जो ISO अप्रूव्ड है। यह मध्यप्रदेश की एकमात्र नर्सरी है, जिसके पास ग्रस्ज्ज रजिस्ट्रेशन है।%

एक बार के इन्वेस्टमेंट में रेगुलर इनकम

प्रमोद भार्गव बताते हैं कि दो तरह की खेती होती है। एक पारंपरिक और दूसरा व्यवसायिक खेती। पारंपरिक खेती में हर 6 महीने इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। व्यवसायिक खेती में एक बार इन्वेस्टमेंट करना होता है। रिटर्न लगातार मिलता रहता है। किसान अगर आमदनी बढ़ाने चाहते हैं, तो आधुनिक खेती की तरफ जाना होगा। मेरे एक परिचित हैं, जिनका कुरवाई में फार्महाउस है। उन्होंने मेरी नर्सरी से आम, आंवला और जामफल पौधे लेकर लगाए हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेडिशनल खेती में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। अब अच्छा मुनाफा हो रहा है।

नर्सरी के लिए ऐसे करें शुरुआत

पौधों की नर्सरी शुरू करने से पहले एक जगह का चुनाव कर लें। जहां पौधों को बड़ा कर सकें, जिसकी मिट्टी उपजाऊ हो। शहरों में कई जगह इसे सड़कों के किनारे शुरू किया जाता है, ताकि आने-जाने वाले लोगों की नजर नर्सरी पर पड़े। यदि आपके पास जगह नहीं है,

समय-समय पर सिंचाई जरूरी

नर्सरी के लिए सही तरह से मिट्टी तैयार करने के साथ ही समय-समय पर सिंचाई भी जरूरी होती है। सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी करनी होगी। इसके बाद रासायनिक और जैविक खाद की आवश्यकता होगी, ताकि पौधों को बीमारियों से बचाया जा सके।

ट्रेनिंग भी ले सकते हैं

नर्सरी के लिए ट्रेनिंग ले भी सकते हैं। इसके बारे में बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि प्लांट को उगाने के लिए, उनको बड़ा करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पौधों के प्रकार, कौन से औषधीय पौधे, कौन से सजावटी, वास्तु के अनुसार पौधों की जानकारी और ऐसी तमाम बातें जिनके बारे में ग्राहक आपसे जानकारी ले सकते हैं। पौधे तैयार करने के लिए अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इनमें सीधे बीज से पौधा उगाना, टिशू कल्चर, बडिंग विधि, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग, डिविजन मेथड, कटिंग विधि सहित अलग-अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है।

ऐसे तैयार कर सकते हैं पौधे

बीज से पौधे उगाना: बीज से सीधे पौधे उगाने के लिए पहले मिट्टी तैयार की जाती है। जरूरी है कि सबसे पहले मिट्टी का परीक्षण जरूर करा लें। उसी से तय हो पाएगा कि कौन सा पौधा उस मिट्टी में सर्वाइव कर पाएगा। मिट्टी तैयार करने के बाद उसमें खाद मिलाई जाती है। इसके बाद उसे छोटी-छोटी काली थैलियों में डाला जाता है। इसके बाद बीज डालकर पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके लिए अधिकतर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते हैं। धीरे-धीरे बीज पनपने लगता है और पौधा तैयार हो जाता है। इसके बाद इन्हें गमले में लगाया जा सकता है।

कटिंग विधि: इस विधि में पौधे की टहनी को कुछ इंच लंबाई में काटकर मिट्टी में लगा दिया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार होता है। कटिंग विधि तीन तरह की होती है। स्टेम कटिंग- इस मेथड में पौधे के तने की कम से कम 6 इंच लंबी कटिंग ली जाती है। उसे मिट्टी से भरे गमले में लगा दिया जाता है। कुछ दिन में मिट्टी में अच्छे से जड़ें विकसित हो जाती है। नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। गुलाब, गुड़हल, पुदीना, मनी प्लांट आदि स्टेम कटिंग से उगने वाले पौधे हैं।

लीफ कटिंग: बहुत से पौधों को आप सिर्फ पत्ती से भी उगा सकते हैं। इस विधि में पौधे के पत्ते को काटकर पानी या सीधे मिट्टी में लगा दिया जाता है। कुछ दिनों में पत्ते से जड़ें निकलने लगती हैं। स्नेक प्लांट, जेड प्लांट, बेगोनिया, अफ्रीकन वायलेट आदि पत्ते से उगने वाले पौधे हैं।

रूट कटिंग: इस विधि में पौधे की मिट्टी को खोदकर उसकी स्वस्थ जड़ को 3 इंच लंबाई में काट लेते हैं। अगर जड़ पतली है, तो उसे मिट्टी में सीधा रख कर 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। अगर जड़ मोटी है, तो उसे मिट्टी में खड़े में लगाया जाता है। जहां से जड़ को काटा था, उस सिरे से तना निकलता है। धीरे-धीरे एक नया पौधा तैयार हो जाता है। गुलाब, फ्लॉक्स, रस्पबेरी, ब्लैकबेरी, साल्विया आदि पौधे जड़ या रूट कटिंग विधि से उगाए जाते हैं।

डिविजन मेथड: कई बारहमासी पौधे जो सालों-साल चलते हैं। डिविजन मेथड से उगाए जाते हैं। इस विधि में मुख्य पौधों के बाजू में जो छोटे-छोटे पौधे उगते हैं, उन्हें उखाड़कर अलग गमले में लगाया जाता है। या कंद से उगने वाले पौधे भी डिविजन मेथड में ही शामिल हैं।

पौधे उगाने की डिविजन विधि के निम्न प्रकार होते हैं: रनर या स्टोलन- कुछ झाड़ीदार पौधे जैसे- स्ट्रॉबेरी, रस्पबेरी, ब्लैकबेरी आदि के तने मिट्टी की सतह पर फैले होते हैं, मिट्टी के सम्पर्क में आने से इनकी नोड्स में से जड़ें निकलनी शुरू हो जाती हैं। नया पौधा तैयार होने लगता है।

सकर्स: एलोवेरा, स्नेक प्लांट जैसे कुछ पौधों के बीच में से छोटे-छोटे पौधे निकलते हैं, जिन्हें सकर्स कहा जाता है। इन सकर्स को अलग करके मिट्टी में लगा दिया जाता है, जिससे नया पौधा तैयार होता है।

ऑफसेट: कुछ पौधे (जैसे पीस लिली, स्नेक प्लांट, केला इत्यादि) जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, तब उनकी जड़ों से ही नए पौधे उगने लगते हैं, जिन्हें ऑफसेट कहा जाता है। इन ऑफसेट को अलग कर नए गमले में लगा देते हैं, जिससे नए पौधे तैयार हो जाते हैं।

ग्राफ्टिंग: यह ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें दो प्रजातियों के पौधों की मदद से नई प्रजाति का पौधा तैयार करते हैं। इसमें एक पौधा जड़ समेत लिया जाता है। दूसरी प्रजाति के पौधे को कलम के रूप में लिया जाता है। कलम वाले भाग को पौधे के तने से जोड़ दिया जाता है। इससे दोनों नए रूप में ग्रो करने लगते हैं। गुलाब, सेब, आम, जामुन और संतरे जैसे कई पौधे ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किए जा सकते हैं। तैयार किए गए नए पौधे में दोनों पौधों के गुण होते हैं।

लेयरिंग: इस तकनीक में पौधे की जमीन के नजदीक वाली और झुकी हुई लचीली शाखा को मोड़कर मिट्टी में दबा दिया जाता है। इससे कुछ दिनों में ही उस शाखा में से जड़ें बनने लगती हैं और नया पौधा तैयार होने लगता है। पौधा बनने के बाद शाखा के उस हिस्से को काट दिया जाता है, जो मुख्य पौधे से जुड़ा है। अब इसे नए पौधे के रूप में विकसित होने दिया जाता है या उखाड़कर गमले में लगा देते हैं। इसे 'लेयरिंग विधि' कहा जाता है। इस तरह लेयरिंग विधि में एक पौधे से कई पौधे तैयार किए जा सकते हैं। लेयरिंग मेथड से स्ट्राबेरी, गुलाब और बोगनविलिया के पौधे उगाए जा सकते हैं।

बडिंग विधि: इसमें भी एक पौधा जड़ सहित लिया जाता है और दूसरे पौधे की कलम के गांठ वाले हिस्से को लिया जाता है। जड़ वाले पौधे के तने में चाकू की मदद से ज्ज आकार का 2 सेंटीमीटर लम्बा कट बनाते हैं। अब दूसरे पौधे से कलम लेते हैं और उसके गांठ वाले हिस्से को 1 सेंटीमीटर तक छील कर उसके अंदर मौजूद सफेद हिस्से को निकाल देते हैं। अब जो 1 सेंटीमीटर लम्बी छाल होती है, उसे जड़ वाले पौधे के ज्ज शेप में लगा देते हैं। इससे कुछ दिनों बाद उस जगह से नई टहनी निकलने लगती है और नया पौधा बनने लगता है।

टिशू कल्चर विधि: यह पौधे उगाने की सबसे नई तकनीक है। इस विधि में पौधे के किसी भाग जैसे पत्ती, फल या फूल को लेकर उसे लैब में ग्रो किया जाता है। पौधे के उस भाग को लैब में विशेष अनुकूल परिस्थितियां जैसे उचित तापमान और लाइट में रखा जाता है। इससे नया पौधा तैयार होने लगता है। इस विधि में पौधे के ऊतक या कोशिका को उगाया जाता है। इस वजह से इसे 'टिशू कल्चर विधि' कहा जाता है।

प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम का लखनऊ में हुआ आयोजन

प्राकृतिक खेती से बिना केमिकल व बिना फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किए बढ़ेगी खेतों की पैदावार: श्री चौहान

प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को तीन साल तक मिलेगी सब्सिडी : चौहान

लखनऊ। जागत गांव हमार

राजधानी लखनऊ में प्राकृतिक खेती के विज्ञान पर क्षेत्रीय परामर्श कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के धरती मां को रसायनों से बचाने के स्वप्न को पूरा करते हुए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में किसान रसायन मुक्त खेती करें ताकि आने वाली पीढ़ी स्वस्थ्य रहे। उन्होंने देश के किसानों का आह्वान किया कि वे अपने खेत के एक हिस्से पर प्राकृतिक खेती करें। श्री सिंह ने कहा कि शुरुआती तीन सालों में जब किसान प्राकृतिक खेती करेंगे तो पैदावार कम होगी और ऐसी स्थिति में सरकार किसानों को सब्सिडी देगी। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से उगाए हुए अनाजों, फलों और सब्जियों की बिक्री से किसानों को डेढ़ गुना ज्यादा दाम मिल जायेंगे। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि देश के कृषि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती के अध्ययन व खोज के लिए प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाएगा जिनकी मदद से देश में प्राकृतिक खेती को मदद मिलेगी और अन्न के भंडार भी भरेंगे।

देश के एक करोड़ किसानों को किया जाएगा जागरूक

श्री सिंह ने कहा कि देश के एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि वे देश के हर कोने में जाकर इसका प्रचार कर सके। उन्होंने कहा कि कहा कि केंद्र सरकार सभी हितधारकों से परामशज करके प्राकृतिक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाएगी। गुजरात के राज्यपाल श्री आचायज देवव्रत ने अपने संबोधन में कहा कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती दो अलग-अलग चीजें हैं और इस अंतर को समझना जरूरी है। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती में पानी की कम जरूरत होती है और यह किसानों के लिए काफी फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि अब सरकार प्राकृतिक खेती के महत्व को समझ गई है।

सभी कृषि विश्वविद्यालयों को दिए गए निर्देश

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक खेती के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सभी छह कृषि विश्वविद्यालयों को प्रमाणन प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में चार कृषि विश्वविद्यालय, 89 कृषि विज्ञान केंद्र और दो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं।

सूअरों और मवेशी चरकर बर्बाद कर रहे किसानों की फसल

अन्नदाता के लिए सौगात के बजाय अभिशाप बना सीप नदी पर बना पुल

श्योपुर। जागत गांव हमार

शहर के वार्ड क्रमांक-1 किला बस्ती राम जानकी मंदिर के पास से मलपुरा गांव जाने के लिए जिस पुल का निर्माण किया गया है वो पुल मलपुरा गांव के किसानों के लिए सौगात के बजाय उल्टा अभिशाप बन गया है। दरअसल, जब से नदी पर यह पुल बना है तब से शहर के आवारा मवेशी और सूअर गांव में प्रवेश कर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं।

शहर में विचरण करने वाले आवारा मवेशी जिनमें अधिकतर संख्या निराश्रित गोवंश की है उनका नया ठिकाना इन दिनों मलपुरा गांव बन गया है। किला रामजानकी मंदिर के पास पुल से होते हुए मवेशी गांव में प्रवेश कर रहे हैं और खेतों में खड़ी फसलों को चरकर बर्बाद कर रहे हैं। इस गांव में रहने वाले ग्रामीण छोटे किसान है जो नदी किनारे अपनी जमीन में सब्जियां उत्पादन करते हैं। सब्जियों को सबसे अधिक बर्बादी सूअर कर रहे हैं मवेशियों की तरह सूअर भी पुल पार कर गांव में घुस रहे हैं जो खेतों में आलू एवं दूसरी सब्जियों को जमीन से खोदकर बर्बाद कर रहे हैं।

किसानों ने मवेशियों को रोकने के उद्देश्य से इस पुल पर बेरिकेट भी लगाए थे, लेकिन इस पुल से आधा दर्जन के करीब गांवों के लोगों का आना जाना बना रहता है इसलिए हमेशा बेरिकेट भी नहीं लगाए जा सकते हैं। जिस कारण किसानों को रात-रात भर पुल पर और अपने खेतों पर जाग कर चौकीदारी करनी पड़ रही है। लेकिन इसके बाद भी मवेशियों के द्वारा उनकी फसल को बबार्द करने का सिलसिला नहीं रुक रहा है।

न ही विकसित हुई चौपाटी और न बसा हॉकर्स जोन

श्योपुर। जागत गांव हमार

शहर में यातायात की समस्या से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से प्रशासन ने कई बार दूरगामी योजनाएं बनाई, लेकिन जिम्मेदारों की इच्छा शक्ति के अभाव में यह योजनाएं जितनी जोर-शोर से शुरू की गई उतनी ही तेजी के साथ खत्म भी हो गई। शहर में यातायात की समस्या को देखते हुए कई बार कलेक्टरों ने इस समस्या के निराकरण के लिए योजनाएं बनाई, लेकिन उक्त योजना को अमल में लाने के लिए मुख्य एजेंसी नगर पालिका की लगातार उदासीनता के चक्कर में योजनाएं शुरू होते ही दम तोड़ चुकी हैं। कई बार फल व्यवसाइयों और चाट ठेले वालों को दूसरे स्थान पर शिफ्ट करने, दो पहिया ती पहिया और चार पहिया वाहनों की अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था करने सड़कों पर बैठकर व्यवसाय करने वालों को हॉकर्स जोन में शिफ्ट करने जैसी योजनाएं बनाकर शहर की अव्यवस्थित यातायात व्यवस्था को ढर्रे पर लाने का प्रयास किया गया, लेकिन ना तो फल, चाट ठेले वाले कहीं शिफ्ट हुए और ना ही हॉकर्स जोन में फेरी वाले पहुंचे।

दो साल पहले तत्कालीन कलेक्टर शिवम वर्मा ने पाली रोड 6 मजार के पास स्थित पुराना बस स्टैंड पर चौपाटी सजाने की कवायद की थी उतनी ही तेजी से यह योजना बंद भी हो गई। आश्चर्य की बात तो यह है कि बाजार से अतिक्रमण का दबाव समाप्त करने के उद्देश्य कलेक्टर के निर्देश पर यह कवायद की थी लेकिन नगरपालिका परिषद की कमजोर इच्छा शक्ति के चलते यह कवायद फलीभूत नहीं हो सकी। तत्कालीन कलेक्टर शिवम वर्मा ने नगर पालिका को पार्किंग स्थल विकसित करने एवं हाथ ठेलों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए थे। कलेक्टर ने इसके लिए सीएमओ को पार्किंग स्थल और हाथ ठेलों को व्यवस्तिथ करने के लिए स्थान भी सुझाय थे।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)